web: www.nyaysakshi.com ‖ पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल ‖ पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, गुरुवार 13 मई 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 222

महत्वपूर्ण एवं खास

चिकित्सा योग्यता प्राप्त सभी कर्मचारी कर सकेंगे चिकित्सकीय कार्य

नई दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्र ने देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए बुधवार को चिकित्सा क्षेत्र में मान्यता प्राप्त योग्यता वाले अपने कर्मचारियों को चिकित्सकीय कार्य करने या फोन पर उपचार संबंधी सलाह देने की अनुमति दे दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जारी किए गए एक आदेश में किया गया कि ये कार्य खाली समय में और विशुद्ध रूप से धर्मार्थ कार्य के रूप में किए जाएं। गृह मंत्रालय के 57 साल पुराने आदेश का हवाला देते हुए डीओपीटी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक महामारी के दौरान केन्द्र सरकार के कई कर्मचारी फोन पर उपचार संबंधी सलाह देने का अनुरोध कर रहे हैं। देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर, संक्रमण से निपटने के लिए सरकार के भीतर मौजूद क्षमताओं का इस्तेमाल करने और जनता की सहायता के लिए यह फैसला किया गया है कि केन्द्र सरकार के वे कर्मचारी, जिनके पास चिकित्सा की किसी भी प्रणाली में मान्यता प्राप्त योग्यता हो उन्हें चिकित्सकीय कार्य करने या फोन पर उपचार संबंधी सलाह देने के लिए विभाग के प्रमुख (एचओडी) से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आईटीबीपी की भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने को दी मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मसूरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) की 1500 वर्ग मीटर भूमि को उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे राज्य सरकार वहां अपनी एक आधारभूत परियोजना- देहरादून और मसूरी के बीच हवाई यात्री रोपवे प्रणाली (एरियल पैसेंजर रोपवे सिस्टम) का निर्माण कर सकेगी। प्रस्तावित रोपवे 5580 मीटर लंबाई का मोनो-केबल रोपवे है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत बनेगा। इसका निचला टर्मिनल स्टेशन देहरादून के पुर्कुल गांव में होगा और ऊपरी टर्मिनल स्टेशन लाइब्रेरी, मसूरी में होगा। 285 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस रोपवे की ढुलाई क्षमता दोनों दिशाओं से 1000 यात्री प्रति घंटा होगी। इससे देहरादून और मसूरी के बीच सड़क मार्ग पर होने वाले यातायात में काफी कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना से 350 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने के साथ ही 1500 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

भारतीय नौसेना ने कोविड केयर केंद्र की स्थापना की

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोनावायरस की दूसरी विनाशकारी लहर से निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने भी कमर कस कर आम आदमियों के लिए भीमूनिपट्टनम में आईएनएस कलिंग, भीमूनिपट्टनम में 60 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया है। इस सुविधा को आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री तथा भीमूनिपट्टनम के विधायक श्रीमुत्तमसेट्टी श्रीनिवासाराव ने दिनांक 11 मई 2021 को जनता को समर्पित किया। आईएनएस कलिंग के कमांडिंग ऑफिसर ने बताया कि कोविड केयर सेंटर में भीमूनिपट्टनम मंडल और आसपास के क्षेत्रों के मध्यम लक्षणों वाले कोविड पॉजिटिव मरीजों को इलाज उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। भारतीय नौसेना द्वारा प्रशासकीय व लॉजिस्टिक सहारा एवं भोजन संरक्षण संबंधी सेवाएं तथा चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोविड केंद्र में तीन डॉक्टर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए 10 नर्सिंग स्टाफ की तैनाती होगी। कोविड केयर केंद्र के रखरखाव और संचालन के लिए पर्यटन मंत्री एवं ज़िला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जी सूर्यनारायण की उपस्थिति में आईएनएस कलिंग के कमांडिंग अधिकारी कमांडर नीरज उदय व भीमूनिपट्टनम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक के बीच एक समझौता पत्रक (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।कोविड केयर सेंटर में हल्के से मध्यम लक्षणों वाले रोगियों की देखभाल करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं हैं। 60 में से 14 बेड में सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के जरिए ऑक्सीजन सपोर्ट की व्यवस्था है।

देश में कोरोना से बढ़ते मौतों ने बढ़ाई चिंता, एक दिन में 4205 की मौत, नए मामलों में आई गिरावट

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामलों में गिरावट आई, लेकिन एक दिन में सर्वाधिक 4,205 लोगों की मौत के आंकड़े ने चिंता को बढ़ाना शुरू कर दिया है। देश में पिछले 24 घंटे में 3.48 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किये गये, जबकि चार हजार से हुई मौत कोरोना संक्रमण को लेकर भय का वातावरण तैयार कर रहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के कारण 4,205 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसके बाद देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,54,197 हो गई है। इनमें से 50 हजार मौतें पिछले 14 दिनों में हुई हैं और मौत का औसत रोजाना

3528 है। जबकि इन 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के के 3,48,371 नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,33,40,938 पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में उपचाराधीन मामले कम होकर 37,04,099 हो गए, जो संक्रमण के कुल मामलों का 15.87 प्रतिशत है, जबकि संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर सुधरकर 83.04 प्रतिशत हो गई है। आंकड़ों के अनुसार अब तक 1,93,82,642 लोग संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि मृत्युदर 1.09 प्रतिशत है।

इनमें से 50 हजार मौतें पिछले 14 दिनों में हुई हैं। मौत का औसत रोजाना 3528 है।

नौ राज्यों में सर्वाधिक मौतें

हालांकि बीते 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में भी कमी आई है। सक्रिय मामलों की संख्या 4000 कम होकर 3.71 पर पहुंच गई है। वहीं महाराष्ट्र में मंगलवार को 793 लोगों की मौत हुई जबकि पिछले दो दिन से 600 से कम लोगों की मौत हो रही थी। मंगलवार को नौ राज्यों में किसी भी एक दिन सर्वाधिक मौतें हुई हैं। इनमें से तमिलनाडु में मौत का आंकड़ा 241 से 298 पहुंच गया।

■ **महाराष्ट्र में 793 मरीजों की मौत-** देश में पिछले 24 घंटे में कुल 4208 मौतों में से महाराष्ट्र में सर्वाधिक 793 मरीजों ने दम तोड़ा। देश में अब तक कुल 2,54,197 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से महाराष्ट्र में 77,191, दिल्ली में 20,010, कर्नाटक में 19,852, तमिलनाडु में 16,178, उत्तर प्रदेश में 16,043, पश्चिम बंगाल में 12,593, छत्तीसगढ़ में 10,941 और पंजाब में 10,918 लोगों की मौत हुई है।

■ **एक दिन में 71,966 लोगों ने दी कोरोना को मात-** देश में इस दौरान विभिन्न अस्पतालों से 71,966 और मरीजों को छुट्टी मिलने के साथ अब तक 45,41,391 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 5,58,996 है। सोमवार को 31 मार्च के बाद पहली बार कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या 40 हजार से कम रही थी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 87.67 प्रतिशत हो गयी है जबकि मृत्यु दर 1.49 बनी हुई है।

■ **तीस करोड़ से ज्यादा जांच-** भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक 11 मई तक 30,75,83,991 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 19,83,804 नमूनों की जांच मंगलवार को की गई। जिन 4,205 और लोगों की मौत हुई है, उनमें से महाराष्ट्र में 793, कर्नाटक में 480, दिल्ली में 347, उत्तर प्रदेश में 301, तमिलनाडु में 298, पंजाब में 214, छत्तीसगढ़ में 199, राजस्थान में 169, हरियाणा में 144, पश्चिम बंगाल में 132, गुजरात और उत्तराखंड में 118-118, आंध्रप्रदेश में 108 और झारखंड में 103 लोगों की मौत हुई है।

■ **जून तक दोगुना होगा कोवाक्सीन का उत्पादन-** केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तीसरे चरण के तहत कोविड सुरक्षा मिशन शुरू करने जा रही है। इस संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि इस मिशन के तहत कोवाक्सीन टीके की वर्तमान उत्पादन क्षमता मई-जून 2021 तक दोगुनी हो जाएगी। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तीसरे चरण के मिशन के तहत टीके का उत्पादन बढ़ाया जाएगा।

भारत में बच्चों के लिए कोवैक्सिन के ट्रायल की इजाजत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में जारी कोरोना की दूसरी लहर के बीच सबसे ज्यादा चिंता बच्चों को लेकर जताई जा रही है। इसका करण यह है कि अभी तक देश में सिर्फ 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही वैक्सीन की डोज दी जा रही है। हालांकि अमेरिका ने कल ही अपने देश में बच्चों के लिए बनी एक वैक्सीन के आपातकाली इस्तेमाल की मंजूरी दी है। अब भारत में भी इसकी उम्मीद जगी है।

भारत बायोटेक और आईसीएमआर के सहयोग से तैयार कोवैक्सिन को 2 साल से 18 साल के बच्चों के लिए ट्रायल की मंजूरी दे दी है। एक विशेषज्ञ समिति ने मंगलवार को 2-18 आयुवर्ग के लिए भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के दूसरे/तीसरे चरण के लिए क्लीनिकल टेस्ट की सिफारिश की थी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह परीक्षण दिल्ली एवं पटना के एम्स और नागपुर स्थित मेडिट्रिना चिकित्सा विज्ञान संस्थान समेत विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा।

केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की कोविड-19 विषय विशेषज्ञ समिति ने मंगलवार को भारत बायोटेक द्वारा किए गए उस आवेदन पर विचार-विमर्श किया। इसमें कोवैक्सीन टीके की दो साल से 18 साल के बच्चों में सुरक्षा और रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने समेत अन्य चीजों का आकलन करने के लिए परीक्षण के दूसरे/तीसरे चरण की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। एक सूत्र ने कहा कि कंपनी के आवेदन पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने प्रस्तावित दूसरे/तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दिए जाने की सिफारिश की थी।

केंद्र ने तीसरे चरण में राज्यों के लिए तय किया वैक्सीन का कोटा

» इस माह 18+ वालों के लिए खरीद सकते हैं सिर्फ दो करोड़ डोज

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों का टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। वहीं देश के दिनों राज्यों में कोविड वैक्सीन की भारी किल्लत होने के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वैक्सीन वितरण का फॉर्मूला शेयर किया है। इसके तहत राज्य सरकारों को 18-44 आयु वर्ग की आबादी के लिए मई

में केवल 2 करोड़ खुराक ही दी जाएंगी।

केंद्र सरकार के मुताबिक मई में राज्यों को 18-44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए सिर्फ दो करोड़ डोज ही दी जाएंगी। केंद्र ने कहा कि इस महीने वैक्सीन की 8.5 करोड़ खुराक उत्पादन होने की उम्मीद है। केंद्र ने कहा कि वह उन खुराकों के लिए भी कोटा तय कर चुका है कि जो राज्यों द्वारा सीधे वैक्सीन निर्माताओं से खरीदने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने कहा कि मई में 18-44 आयु वर्ग के लोगों के लिए राज्यों को वैक्सीन की दो करोड़ की डोज भेजी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैक्सीन डोज का समान रूप से वितरण हो। आपको बता दें कि कुछ राज्यों ने शिकायत की है कि उनका आवंटन अपर्याप्त है।बता दें कि सरकारी आंकड़े के मुताबिक, देश में 18 से 44 वर्ष के बीच के लगभग 59.5 करोड़ लोग हैं।

■ **सभी राज्यों को वैक्सीन डोज जरुरी-** केंद्र सरकार ने बीते हफ्ते के अंत में सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रतिक्रिया दाखिल की गई है। इसमें कहा कि राज्य निर्माताओं से टीकों की खरीद कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं से परामर्श करके प्रत्येक राज्य की 18-44 आयु वर्ग की आबादी के आधार पर कोटा निर्धारित किया है। राज्य केवल तय मात्रा में वैक्सीन की डोज ही खरीद करेंगे ताकि राज्यों के बीच टीके की उपलब्धता में कोई असमानता न हो।

अब देश में गांवों में भी पैर पसारने लगा कोरोना वायरस

» ग्रामीण इलाकों में संक्रमण बढ़ने से राज्य सरकारें चिंतित

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश के शहरी क्षेत्रों में भले ही रोजाना नए कोरोना मामलों की संख्या में कमी आने लगी हो, लेकिन देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना वायरस ने ग्रामीण क्षेत्रों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसके विपरीत राज्यों में अब शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि गांवों में अपेक्षित स्तर पर कोरोना टेस्ट हो ही नहीं रहे हैं। इस कारण कई पॉजिटिव केस सरकारी आंकड़ों में शामिल ही नहीं हो पा रहे। चूंकि ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा व्यवस्था भी लगभग चौपट है, इसलिए वहां दम तोड़ने वाले

मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है।

■ **इन 13 राज्यों में ग्रामीण इलाकों से आ रहे ज्यादा केस-** जिन 24 राज्यों में जिलों को ग्रामीण और शहरी आधार पर अलग किया जा सकता है, उनमें 13 राज्य ऐसे हैं जहां बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और देहातों से ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं। जब से कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर चली तब से लगभग सभी राज्यों से आने वाले कोरोना केस में ग्रामीण इलाकों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। दैनिक कोरोना केस का अध्ययन करने पर पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज है। इसका कारण यह है कि शहरों में अब केस कम हो रहे हैं जबकि गांवों में अब भी बढ़ रहे हैं। मसलन, बिहार के शहरी क्षेत्र में डेली कोरोना केस का पीक 3,482 था जबकि ग्रामीण क्षेत्र का यह आंकड़ा 10,710 रहा। 9 अप्रैल को यहां कुल कोरोना केस में ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी 53 प्रतिशत थी जो 9 मई को बढ़कर 76 प्रताशत हो गई। नीचे के ग्राफ में ऐसे ही अन्य 12 राज्यों के आंकड़े दिए गए हैं।

■ **इन 11 राज्यों के गांवों दैनिक कोरोना केस में हिस्सेदारी-** देश के 11 ऐसे राज्य हैं जहां अब भी हर दिन शहरों से ज्यादा केस आ रहे हैं, लेकिन अप्रैल से यहां के ग्रामीण इलाकों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। ये वैसे राज्य हैं जहां कोरोना केस में ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों की हिस्सेदारी ज्यादा है। मसलन, पंजाब में 9 अप्रैल को कुल कोरोना केस में गांवों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत थी जो 9 मई को बढ़कर 49 प्रतिशत हो गई। फिर भी ध्यान रखना होगा कि यहां गांवों के मुकाबले शहरों से अब भी ज्यादा केस आ रहे हैं।

■ **जितने केस सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा दर्ज ही नहीं किए जा रहे-** गांवों में ज्यादातर वही लोग टेस्ट करवा रहे हैं जिनमें कोरोना के गंभीर लक्षण दिख रहे हैं। सामान्य लक्षण वाले ज्यादातर लोग जांच ही नहीं करवा रहे। दुनियाभर में पॉजिटिविटी रेट 5 प्रतिशत से नीचे रखने की जद्दोजहद रहती है, लेकिन पुडुचेरी के यमन जिले में यह करीब-करीब 100 प्रतिशत है। पिछले हफ्ते 17 जिलों में 48 प्रतिशत टेस्ट पॉजिटिविटी पाई गई।

डीआरडीओ से ऑक्सीकेयर प्रणाली की डेढ़ लाख इकाई खरीदेगी सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित 'ऑक्सीकेयर' प्रणाली की 1,50,000 इकाई खरीदने के लिए बुधवार को स्वीकृति प्रदान कर दी जिससे कोविड-19 संक्रमित रोगियों के उपचार में सहायता मिलेगी ।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार ऑक्सीकेयर एसपीओ2 पर आधारित एक ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली है। डीआरडीओ ने पहले ही ऑक्सीकेयर प्रणाली के भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिये विविध उद्योगों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया है। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार ऑक्सीकेयर प्रणाली की खरीद पीएम केयर्स फंड का उपयोग करते हुए 322.5 करोड़ रूपये में की जायेगी। इसमें कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड ने डीआरडीओ द्वारा विकसित ऑक्सीकेयर प्रणाली की 1,50,000 इकाई 322.5 करोड़ रूपये में खरीदने को स्वीकृति प्रदान कर दी।

मंत्रालय ने कहा कि 1,00,000 हाथ से उपयोग की जाने वाली और 50,000 स्वचालित ऑक्सीकेयर प्रणाली खरीदी जा रही हैं। ऑक्सीकेयर का विकास डीआरडीओ के बेंगलूरू स्थित रक्षा बायो इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रो चिकित्सा प्रयोगशाला (डीईबीईएल) द्वारा अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिये किया गया है।

विद्युत मंत्रालय देश में ऑक्सीजन संयंत्रों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठा रहा है ठोस कदम

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर देशभर में होने से चिकित्सा जरूरतों और घर में इलाज करा रहे कोरोना रोगियों के उपचार के लिए ऑक्सीजन की मांग में कई गुना वृद्धि हुई है। इसको देखते हुए विद्युत मंत्रालय ने राज्यों के इस्तेमाल में आने वाले ऑक्सीजन संयंत्रों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई ठोस और सुधारात्मक उपाय किए हैं। विद्युत मंत्रालय देश भर में 73 प्रमुख चिन्हित ऑक्सीजन संयंत्रों को बिजली आपूर्ति की निगरानी कर रहा है, जिसमें से 13 ऑक्सीजन संयंत्र एनसीआर क्षेत्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। मंत्रालय द्वारा जो कदम उठाए गए वे हैं

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF POWER

विद्युत सचिव द्वारा दैनिक समीक्षाः सभी ऑक्सजीन संयंत्रों को बिजली आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा विद्युत मंत्रालय के सचिव, राज्यों के संबंधित ऊर्जा सचिवों और पोस्को के सीएमडी द्वारा मिलकर प्रतिदन मामले के आधार पर किया जा रहा है। ऑक्सीजन संयंत्रों को 24×7 बिजली की आपूर्ति से संबंधित सभी मुद्दों पर दैनिक समीक्षा के दौरान चर्चा की जाती है और पोस्को और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सहायता प्राप्त राज्य डिस्कॉम के माध्यम से समयबद्ध तरीके से सुधार की योजना बनाई जाती है और इसे क्रियान्वित किया जाता है।

चौबीसों घंटे (आरटीसी) ऑपरेशन रूम का संचालनः सुधारात्मक रणनीति के एक भाग के रूप में, आरईसी लिमिटेड में एक 24 घंटे ऑक्सीजन प्लांट कंट्रोल रूम (ओपीसीआर) और एक आंतरिक नियंत्रण समूह (आईसीजी) की स्थापना की गई है, जिसे इन प्लांट्स को 24ङ्क7 बिजली आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन प्लान के नोडल अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखने का काम सौंपा गया है। बिजली आपूर्ति में कहीं रुकावट आने पर तत्काल समाधान के लिए डिस्कॉम और इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन साइड द्वारा मिलकर कदम उठाया जा रहा है। राज्यों (एसटीयू एंड डिस्कॉम), एसएलडीसी और पावरग्रिड के साथ पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन (पोस्को) द्वारा विद्युत आपूर्ति में रुकावट आने पर उसका तत्काल विश्लेषण किया जाता है और उसके समाधान के लिए सलाह जारी किए जाते हैं।

विद्युत आपूर्ति 24×7 सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदमः ऑक्सीजन संयंत्रों को विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को सभी प्रिवेन्टिव कदम उठाने की सलाह जारी की गई है। इसमें अतिरिक्त पावर का निर्माण और ऑक्सीजन संयंत्रों को बिजली की आपूर्ति करने वाले फीडरों का आइसोलेशन शामिल है। सुधारात्मक उपायों में से कुछ में बरोटीवाला संयंत्र (हिमाचल प्रदेश) और केरल मिनरल और मेटल प्लांट (केरल) में रिले को रीसेट करना शामिल है; और बर्ड फॉल्ट की संभावना वाले सेलक्की (उत्तराखंड) में ऑक्सीजन प्लांट के लिए 132केवी भूमिगत केबल बिछाना शामिल है।

■ **विद्युत आपूर्ति की तकनीकी ऑडिट और सुधारात्मक उपायों का सक्रिय कार्यान्वयन-** पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन (पोस्को) को विशेष रूप से एनसीआर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले प्रत्येक ऑक्सीजन संयंत्रों की बिजली आपूर्ति की तकनीकी ऑडिट करने का काम सौंपा गया है। ऑडिट में बिजली आपूर्ति की श्रेणी, बिजली आपूर्ति के स्रोत का आकलन करना, वैकल्पिक व्यवस्था की उपलब्धता, रिले सेटिंग्स आदि शामिल हैं। ऑडिट रिपोर्ट में छोटी और लंबी अवधि के उपायों के साथ-साथ बिजली की आपूर्ति में सुधार हैं। अब तक, दिल्ली और एनसीआर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले 13 संयंत्रों का ऑडिट किया गया है। तकनीकी ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर, विद्युत मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को पत्र लिखा है, जिसमें उन कदमों को उठाने के बारे में बताया गया है जिससे संबंधित राज्यों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।